Weekly One Liners 27th January to 2nd February 2025

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: मुख्य बातें

भारत का आर्थिक सर्वे 2025 भारत की आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रमुख प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ और सतत विकास के लिए नीति सिफारिशें शामिल हैं। केंद्रीय बजट से पहले प्रस्तुत इस सर्वे में वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की लचीलापन को रेखांकित किया गया है, जिसमें मजबूत जीडीपी वृद्धि, घटती महंगाई और विनिर्माण, सेवाओं और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रमुखता दी गई है। यह रोजगार सृजन, वित्तीय समायोजन और हरित ऊर्जा संक्रमण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी संबोधित करता है, और सरकार के दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समावेशिता प्राप्त करने के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी आनंदा नागेश्वरन ने इस आर्थिक सर्वे पर प्रस्तुति दी।

आर्थिक सर्वे 2025 के प्रमुख बिंदु

अध्याय 1: अर्थव्यवस्था की स्थिति: तेज़ी से पटरी पर लौटना

- भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि FY25 में 6.4 प्रतिशत अनुमानित है (राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार), जो इसके दशकीय औसत के लगभग समान है।
- वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (GVA) भी FY25 में 6.4 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में औसतन 3.3 प्रतिशत बढ़ी, जबकि IMF ने अगले पांच वर्षों में 3.2 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।
- FY26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है, यह ध्यान में रखते हुए कि वृद्धि के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं।
- मध्यमकालिक विकास क्षमता को सुदृढ़ करने और भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधारों और विनियमन में ढील पर जोर दिया गया है।
- वैश्विक राजनीतिक तनाव, चल रहे संघर्ष और वैश्विक व्यापार नीति के जोखिम वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बने हुए हैं।
- रिटेल हेडलाइन मुद्रास्फीति FY24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर अप्रैल – दिसम्बर 2024 में 4.9 प्रतिशत हो गई है।
- पूंजीगत व्यय (CAPEX) FY21 से FY24 तक लगातार बढ़ा है। सामान्य चुनावों के बाद, जुलाई – नवम्बर 2024 के दौरान CAPEX में साल दर साल 8.2 प्रतिशत वृद्धि हुई।
- भारत वैश्विक सेवाओं के निर्यात में सातवें-largest हिस्से का योगदान देता है, जो इस क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है।
- अप्रैल से दिसम्बर 2024 के दौरान, गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो वैश्विक परिस्थितियों में भारत के माल निर्यात की लचीलापन को प्रदर्शित करता है।

अध्याय 2: मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास

- बैंक ऋण में स्थिर दर से वृद्धि हुई है तथा ऋण वृद्धि जमा वृद्धि के अनुरूप हो गई है।
- निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता में सुधार हुआ, जो सकल गैर-निष्पादित संपत्तियों (GNPAs) में गिरावट और पूंजी-जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (CRAR) में वृद्धि के रूप में प्रदर्शित हुआ।
- ऋण वृद्धि ने दो लगातार वर्षों तक नाममात्र जीडीपी वृद्धि को पीछे छोड़ा। ऋण-जीडीपी अंतर Q1 FY25 में (-) 0.3 प्रतिशत से घटकर Q1 FY23 में (-) 10.3 प्रतिशत हो गया, जो स्थिर बैंक ऋण वृद्धि को दर्शाता है।
- बैंकिंग क्षेत्र में संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार, मजबूत पूंजी बफर और मजबूत संचालन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है।
- निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित संपत्तियां (GNPAs) सितंबर 2024 के अंत में 2.6 प्रतिशत के 12 साल के न्यूनतम स्तर तक गिर गईं।
- दीवालियापन और दिवालियापन संहिता (IBC) के तहत, सितंबर 2024 तक 1,068 योजनाओं के समाधान से ₹3.6 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई। यह परिसंपत्तियों के विनिर्माण मूल्य के मुकाबले 161 प्रतिशत और सही मूल्य के 86.1 प्रतिशत के बराबर है।
- भारतीय स्टॉक बाजार ने चुनावी बाजार उतार-चढ़ाव की चुनौतियों के बावजूद उभरते बाजारों के समकक्ष प्रदर्शन किया।
- प्राथमिक बाजारों (इक्विटी और ऋण) से कुल संसाधन जुटाने की राशि अप्रैल से दिसंबर 2024 तक ₹11.1 लाख करोड़ रही, जो FY24 के मुकाबले 5 प्रतिशत अधिक है।
- BSE स्टॉक बाजार पूंजीकरण-से-GDP अनुपात दिसंबर 2024 के अंत में 136 प्रतिशत रहा, जो चीन (65 प्रतिशत) और ब्राजील (37 प्रतिशत) जैसे अन्य उभरते बाजारों से कहीं अधिक है।
- भारत का बीमा बाजार अपनी ऊपर की ओर वृद्धि जारी रखे हुए है, FY24 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7 प्रतिशत बढ़कर ₹11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गए।
- भारत के पेंशन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, सितंबर 2024 तक पेंशन उपभोक्ताओं की संख्या में 16 प्रतिशत (YoY) वृद्धि हुई।

अध्याय 3: बाह्य क्षेत्र: एफडीआई को सही दिशा में लाना

- भारत का बाह्य क्षेत्र वैश्विक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बीच भी लचीलापन दिखाता है।
- कुल निर्यात (वस्त्र + सेवाएं) FY25 के पहले नौ महीनों में 6 प्रतिशत (YoY) बढ़ा। सेवाओं के क्षेत्र में इस दौरान 11.6 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- भारत 'दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं' के वैश्विक निर्यात बाजार में 10.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है, जैसा कि UNCTAD द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
- भारत का चालू खाता घाटा (CAD) FY25 की दूसरी तिमाही में GDP का 1.2 प्रतिशत था, जो बढ़ते शुद्ध सेवा प्राप्तियों और निजी स्थानांतरण प्राप्तियों में वृद्धि से समर्थित था।
- कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रवाह में FY25 में पुनरुद्धार देखा गया, जो FY24 के पहले आठ महीनों में USD 47.2 बिलियन से बढ़कर FY25 के समान अवधि में USD 55.6 बिलियन हो गया, जो YoY 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
- भारत का FOREX भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक USD 640.3 बिलियन रहा, जो 10.9 महीने के आयात को कवर करने और देश के बाह्य ऋण का लगभग 90 प्रतिशत कवर करने के लिए पर्याप्त है।
- भारत का बाह्य ऋण पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा है, और सितंबर 2024 के अंत तक बाह्य ऋण-से-GDP अनुपात 19.4 प्रतिशत था।

अध्याय 4: मूल्य और मुद्रास्फीति: गतिशीलता को समझना

- IMF के अनुसार, वैश्विक मुद्रास्फीति दर 2024 में 5.7 प्रतिशत तक घट गई, जो 2022 में 8.7 प्रतिशत के शिखर से कम हुई।
- भारत में खुदरा मुद्रास्फीति FY24 में 5.4 प्रतिशत से घटकर FY25 (अप्रैल-दिसंबर 2024) में 4.9 प्रतिशत हो गई।
- RBI और IMF का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति धीरे-धीरे FY26 में लगभग 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएगी।
- जलवायु परिवर्तन-रोधी फसलों की किस्मों और उन्नत कृषि पद्धतियों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि चरम मौसम घटनाओं के प्रभावों को कम किया जा सके और दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता प्राप्त की जा सके।

अध्याय 5: मध्यकालीन दृष्टिकोण: वृद्धि को बढ़ावा देने में नियमन में छूट

- भारतीय अर्थव्यवस्था एक बदलाव के मध्य में है जो एक अभूतपूर्व आर्थिक चुनौती और अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। भू-आर्थिक विखंडन (GEF) वैश्वीकरण को बदल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक पुन: समायोजन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है।
- 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए भारत को लगभग एक या दो दशकों तक निरंतर मूल्य पर लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी।
- भारत का मध्यकालीन वृद्धि दृष्टिकोण नए वैश्विक वास्तविकताओं – GEF, चीन की विनिर्माण क्षमता, और ऊर्जा संक्रमण के प्रयासों में चीन पर निर्भरता – को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए।
- भारत को घरेलू वृद्धि के यंत्रों को पुनर्जीवित करने और व्यक्तियों तथा संगठनों को वैध आर्थिक गतिविधियों को आसानी से करने के लिए व्यवस्थित नियमन में छूट पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
- व्यवस्थित नियमन में छूट या व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, भारतीय अर्थव्यवस्था के मध्यकालीन विकास संभावनाओं को मजबूत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण नीति प्राथमिकता मानी जा सकती है।
- अब सुधारों और आर्थिक नीतियों का ध्यान Ease of Doing Business 2.0 के तहत व्यवस्थित नियमन में छूट और भारत के SME क्षेत्र यानी Mittelstand के निर्माण पर होना चाहिए।
- अगले कदम के रूप में, राज्यों को मानकों और नियंत्रणों को उदारीकरण, कानूनी सुरक्षा उपायों की स्थापना, शुल्क और करों में कमी, और जोखिम-आधारित नियमन लागू करने पर काम करना चाहिए।

अध्याय 6: निवेश और अवसंरचना

- पिछले पांच वर्षों में सरकार का केंद्रीय ध्यान अवसंरचना पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाने और अनुमोदन तथा संसाधन संग्रहण की गति को तेज़ करने पर रहा है।
- संघ सरकार की प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय FY20 से FY24 तक 38.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।
- रेलवे कनेक्टिविटी के तहत, अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को चालू किया गया और अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच 17 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गईं।
- सड़क नेटवर्क के तहत, FY25 (अप्रैल-दिसंबर) में 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ।
- नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, विभिन्न क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उपयोग के लिए चरण 1 में कुल 383 प्लॉट, जिसमें 3788 एकड़ भूमि शामिल है, आवंटित किए गए हैं।
- संचालनात्मक दक्षता में सुधार हुआ है, प्रमुख बंदरगाहों में औसत कंटेनर टर्नअराउंड समय को FY24 में 48.1 घंटे से घटाकर FY25 (अप्रैल-नवंबर) में 30.4 घंटे कर दिया गया, जिससे बंदरगाह कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ।
- नवीनतम ऊर्जा क्षमता में 15.8 प्रतिशत की साल दर साल वृद्धि हुई है, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा में, दिसंबर 2024 तक।
- भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा अब 47 प्रतिशत है।
- सरकार की योजनाओं जैसे DDUGJY और SAUBHAGYA ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंच में सुधार किया, 18,374 गांवों को विद्युतीकरण किया और 2.9 करोड़ Haushholds को बिजली उपलब्ध कराई।
- सरकार की डिजिटल कनेक्टिविटी पहल ने गति पकड़ी है, विशेष रूप से अक्टूबर 2024 तक सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 5G सेवाओं की शुरुआत के साथ।
- यूनीवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (अब डिजिटल भारत निधि) के तहत दूरदराज के क्षेत्रों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के प्रयासों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, दिसंबर 2024 तक 10,700 से अधिक गांवों को कवर किया गया है।
- जल जीवन मिशन के तहत, इसके शुभारंभ से अब तक 12 करोड़ से अधिक परिवारों को पाइप से पीने का पानी उपलब्ध हो चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीन के चरण II के तहत, अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 1.92 लाख गांवों को मॉडल श्रेणी में ODF प्लस घोषित किया गया, जिससे कुल ODF प्लस गांवों की संख्या 3.64 लाख तक पहुंच गई।

- शहरी क्षेत्रों में, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89 लाख से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है।
- शहरों में परिवहन नेटवर्क तेजी से विस्तार कर रहा है, 29 शहरों में मेट्रो और तेज़ रेल प्रणालियाँ चालू हैं या निर्माणाधीन हैं, जो 1,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर कर रही हैं।
- रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 ने रियल एस्टेट क्षेत्र की नियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित की। जनवरी 2025 तक, 1.38 लाख से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाओं को पंजीकृत किया गया है और 1.38 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है।
- भारत वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष संपत्तियों का संचालन करता है। सरकार का अंतरिक्ष विज़न 2047 में गगनयान मिशन और चंद्रयान-4 लूनर सैंपल रिटर्न मिशन जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाएँ शामिल हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश अकेले अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, और इस अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण होगी।
- सरकार ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन जैसी योजनाओं का निर्माण किया है ताकि अवसंरचना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिल सके।

अध्याय 7: उद्योग: व्यवसाय सुधारों के बारे में सब कुछ

- औद्योगिक क्षेत्र में FY25 (पहली अग्रिम अनुमान) में 6.2 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है, जो बिजली और निर्माण में मजबूत वृद्धि द्वारा प्रेरित है।
- सरकार सक्रिय रूप से स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग 4.0 को बढ़ावा दे रही है, SAMARTH उद्योग केंद्रों की स्थापना का समर्थन कर रही है।
- FY24 में, भारतीय ऑटोमोबाइल घरेलू बिक्री में 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- FY15 से FY24 तक, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का घरेलू उत्पादन 17.5 प्रतिशत की सीएजीआर (कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ा है।
- अब 99 प्रतिशत स्मार्टफोन घरेलू रूप से निर्मित होते हैं, जिससे भारत की आयातों पर निर्भरता में भारी कमी आई है।
- FY24 में, फार्मास्यूटिकल्स का कुल वार्षिक कारोबार ₹4.17 लाख करोड़ था, जो पिछले पांच वर्षों में 10.1 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा है।
- WIPO रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत वैश्विक रूप से शीर्ष 10 पेटेंट फाइलिंग कार्यालयों में छठे स्थान पर है।
- सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (MSME) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र बनकर उभरा है।
- MSMEs को इक्विटी फंडिंग प्रदान करने के लिए, जिनके पास विस्तार की क्षमता है, सरकार ने ₹50,000 करोड़ के कोष के साथ आत्मनिर्भर भारत फंड लॉन्च किया।
- सरकार देशभर में क्लस्टरों का विकास करने के लिए माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस- क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू कर रही है।

अध्याय 8: नई चुनौतियाँ

- सेवा क्षेत्र का कुल GVA में योगदान FY14 में 50.6 प्रतिशत से बढ़कर FY25 (पहले अग्रिम अनुमान) में 55.3 प्रतिशत हो गया है।
- सेवा क्षेत्र की औसत वृद्धि दर महामारी से पहले के वर्षों (FY13 - FY20) में 8 प्रतिशत थी। महामारी के बाद की अवधि (FY23–FY25) में यह 8.3 प्रतिशत रही।
- भारत ने 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में 4.3 प्रतिशत हिस्सेदारी रखी, जो इसे दुनिया भर में सातवां स्थान दिलाता है।
- भारत के सेवाओं के निर्यात में अप्रैल–नवंबर FY25 के दौरान 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो FY24 में 5.7 प्रतिशत थी।
- सूचना और कंप्यूटर संबंधित सेवाएँ पिछले दशक (FY13–FY23) में 12.8 प्रतिशत की दर से बढ़ीं, जिससे इनका कुल GVA में हिस्सा 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गया।
- भारतीय रेलवे ने FY24 में यात्रियों के यातायात में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। FY24 में राजस्व अर्जित माल ढुलाई में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- पर्यटन क्षेत्र का GDP में योगदान FY23 में महामारी से पहले के स्तर 5 प्रतिशत पर वापस लौट आया।

अध्याय 9: कृषि और खाद्य प्रबंधन: भविष्य का क्षेत्र

- 'कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ' क्षेत्र FY24 (PE) में देश के GDP का लगभग 16 प्रतिशत योगदान करती हैं, वर्तमान मूल्यों पर।
- उच्च-मूल्य वाले क्षेत्र जैसे बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन समग्र कृषि विकास के प्रमुख चालक बन गए हैं।
- 2024 के खरीफ खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान 1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) है, जो पिछले वर्ष से 89.37 LMT की वृद्धि है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, अरहर और बाजरा का MSP क्रमशः उत्पादन की औसत लागत से 59 प्रतिशत और 77 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
- मत्स्य पालन क्षेत्र ने 8.7 प्रतिशत की सबसे उच्च सामूहिक वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दिखाई, इसके बाद पशुपालन का CAGR 8 प्रतिशत रहा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ने खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव किया।
- PMGKAY के तहत अगले पांच वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने की व्यवस्था, सरकार की खाद्य और पोषण सुरक्षा के प्रति दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
- 31 अक्टूबर तक, 11 करोड़ से अधिक किसान पीएम-किसान योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं, जबकि 23.61 लाख किसान पीएम किसान मानधन योजना में पंजीकृत हैं।

अध्याय 10: जलवायु और पर्यावरण

- भारत का 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य समावेशी और सतत विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है।
- भारत ने 30 नवम्बर 2024 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की है, जो कुल क्षमता का 46.8 प्रतिशत है।
- भारत के वन सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, 2005 से 2024 के बीच 2.29 बिलियन टन CO2 समकक्ष अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण हुआ है।
- भारत द्वारा नेतृत्व किया गया वैश्विक आंदोलन, 'लाइफस्टाइल फॉर एन्वायरनमेंट' (LiFE), देश की स्थिरता प्रयासों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है।
- 2030 तक, अनुमान है कि LiFE उपायों से उपभोक्ताओं को वैश्विक स्तर पर लगभग 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बचत हो सकती है, जिससे उपभोग कम होगा और कीमतें घटेंगी।

अध्याय 11: सामाजिक क्षेत्र - पहुंच का विस्तार और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

- सरकार का सामाजिक सेवा व्यय (केंद्र और राज्यों के संयुक्त रूप में) FY21 से FY25 तक 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।
- गिनी गुणांक, जो उपभोग व्यय में असमानता का माप है, घट रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह 2022-23 में 0.266 से घटकर 2023-24 में 0.237 हो गया, और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 2022-23 में 0.314 से घटकर 2023-24 में 0.284 हो गया।
- सरकार की विभिन्न राजकोषीय नीतियां आय वितरण को पुनः आकार देने में मदद कर रही हैं।
- सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गया है; कुल स्वास्थ्य व्यय में परिवारों द्वारा किए गए खर्च की हिस्सेदारी 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गई है, जिससे घरों पर वित्तीय बोझ कम हुआ है।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) ने ₹1.25 लाख करोड़ की बचत दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- स्थिरता विकास लक्ष्यों (SDGs) का स्थानीयकरण की रणनीति अपनाई गई है ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर बजट SDG उद्देश्यों के साथ मेल खा सके।

अध्याय 12: रोजगार और कौशल विकास: अस्तित्व की प्राथमिकताएँ

- भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है, और बेरोजगारी दर 2017-18 (जुलाई-जून) में 6.0 प्रतिशत से घटकर 2023-24 (जुलाई-जून) में 3.2 प्रतिशत हो गई है।
- भारत में 10-24 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या लगभग 26 प्रतिशत है, जिससे देश दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक बन गया है, और यह एक अनूठे जनसांख्यिकीय अवसर की दहलीज़ पर खड़ा है।
- महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें ऋण तक आसान पहुंच, विपणन समर्थन, कौशल विकास और महिला स्टार्टअप्स को समर्थन शामिल हैं।
- बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर रहे हैं, जो 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए आवश्यक हैं।
- सरकार एक मजबूत और उत्तरदायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर रही है ताकि वैश्विक ट्रेंड्स जैसे स्वचालन, जनरेटिव एआई, डिजिटलीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ तालमेल बैठाया जा सके।
- सरकार ने रोजगार बढ़ाने, स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों की भलाई को बढ़ावा देने के लिए उपायों को लागू किया है।
- हाल ही में शुरू की गई पीएम-इंटर्नशिप योजना रोजगार सृजन के लिए एक परिवर्तनकारी उत्प्रेरक के रूप में उभर रही है।
- ईपीएफओ के तहत शुद्ध पेरोल जोड़ियां पिछले छह वर्षों में दोगुनी हो गई हैं, जो औपचारिक रोजगार में स्वस्थ वृद्धि का संकेत देती हैं।

अध्याय 13: एआई युग में श्रम: संकट या उत्प्रेरक?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के डेवलपर्स एक नए युग की शुरुआत करने का वादा करते हैं, जहां अधिकांश आर्थिक रूप से मूल्यवान काम स्वचालित हो जाएगा।
- एआई को विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान, आपराधिक न्याय, शिक्षा, व्यवसाय, और वित्तीय सेवाओं में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मानव प्रदर्शन को पार करने की उम्मीद है।
- वर्तमान में बड़े पैमाने पर एआई अपनाने के लिए कुछ बाधाएं बनी हुई हैं, जिनमें विश्वसनीयता, संसाधन की अक्षमताएँ, और अवसंरचनात्मक कमी शामिल हैं। ये चुनौतियाँ और एआई की प्रयोगात्मक प्रकृति नीति निर्माताओं के लिए कार्य करने का एक अवसर प्रदान करती हैं।
- सौभाग्य से, चूंकि एआई अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, भारत को अपनी नींव को मजबूत करने और एक राष्ट्रव्यापी संस्थागत प्रतिक्रिया जुटाने के लिए आवश्यक समय मिल रहा है।
- अपने युवा, गतिशील और तकनीकी रूप से सक्षम जनसंख्या का लाभ उठाते हुए, भारत के पास एक ऐसा कार्यबल बनाने की क्षमता है जो एआई का उपयोग अपने काम और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कर सके।
- भविष्य 'ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस' के चारों ओर घूमता है, जहां कार्यबल मानव और मशीन क्षमताओं दोनों को एकीकृत करता है। यह दृष्टिकोण मानव क्षमता को बढ़ाने और नौकरी प्रदर्शन में कुल मिलाकर दक्षता को सुधारने का उद्देश्य रखता है, जो अंततः समाज को समग्र रूप से लाभान्वित करेगा।
- सरकार, निजी क्षेत्र और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोगात्मक प्रयास एआई-प्रेरित परिवर्तन के प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। बजट की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

बजट अनुमान 2025-26

- उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियां ₹34.96 लाख करोड़ और कुल व्यय ₹50.65 लाख करोड़ अनुमानित।
- शुद्ध कर प्राप्तियां ₹28.37 लाख करोड़ होने का अनुमान।
- राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान।
- सकल बाजार उधारी ₹14.82 लाख करोड़ रहने की संभावना।
- पूंजीगत व्यय ₹11.21 लाख करोड़ (GDP का 3.1%) निर्धारित।

विकास का पहला इंजन - कृषि क्षेत्र

- **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना**: 100 कृषि जिलों के विकास हेतु राज्यों के सहयोग से नई योजना, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
- **ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण कार्यक्रम**: कृषि में कौशल विकास, निवेश और तकनीकी सुधार के माध्यम से रोजगार बढ़ाने हेतु एक व्यापक कार्यक्रम।
- **दलहन में आत्मनिर्भरता**: तूर, उड़द और मसूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6-वर्षीय मिशन, जिसमें NAFED और NCCF अगले 4 वर्षों तक किसानों से दलहन की खरीद करेंगे।
- **सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम**: राज्यों के सहयोग से उत्पादन, आपूर्ति, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु योजना।
- **मखाना बोर्ड (बिहार)**: मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना।
- **उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन**: अनुसंधान को मजबूत करने, उच्च उत्पादकता वाले बीज विकसित करने और 100 से अधिक बीज किस्मों की वाणिज्यिक उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मिशन।

- **मत्स्य पालन**: भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन के लिए नीति, विशेष रूप से अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों पर ध्यान केंद्रित।
- **कपास उत्पादकता मिशन**: 5-वर्षीय मिशन, जिससे कपास की उत्पादकता और सतत खेती को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से ऋण सीमा बढ़ोतरी**: संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई।
- **असम में यूरिया संयंत्र**: नामरूप, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

विकास का दूसरा इंजन - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME)

- **MSME वर्गीकरण मानदंड में संशोधन**: MSME की निवेश और टर्नओवर सीमा को 2.5 और 2 गुना बढ़ाया जाएगा।
- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड**: उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
- **स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स**: विस्तारित दायरे और ₹10,000 करोड़ के नए योगदान के साथ नया फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।
- **पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए योजना**: 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नए उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का टर्म-लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- **जूते और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना**: इस क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु योजना, जिससे 22 लाख नौकरियां सृजित होंगी, ₹4 लाख करोड़ का टर्नओवर और ₹1.1 लाख करोड़ का निर्यात लक्ष्य।
- **खिलौना उद्योग के लिए विशेष योजना**: अभिनव, उच्च गुणवत्ता और सतत विकास वाले खिलौनों के निर्माण को बढ़ावा देने और भारत को खिलौना निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए योजना।
- **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सहयोग**: बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना।
- **"मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन**: छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों को कवर करने वाला राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन घोषित।

विकास का तीसरा इंजन - निवेश

जनता में निवेश

- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0**: पोषण सहायता के लिए लागत मानकों को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।
- **अटल टिंकरिंग लैब्स**: अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी।
- **सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी**: भारतनेट परियोजना के तहत सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
- **भारतीय भाषा पुस्तक योजना**: डिजिटल स्वरूप में भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने हेतु योजना की घोषणा।
- **कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र**: "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- **आईआईटी की क्षमता विस्तार**: 2014 के बाद स्थापित 5 आईआईटी में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा विकसित कर 6,500 और छात्रों के लिए शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **एआई शिक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र**: शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ की लागत से एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
- **चिकित्सा शिक्षा का विस्तार**: अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटें बढ़ेंगी।
- **जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र**: अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित होंगे।
- **शहरी आजीविका को सशक्त बनाना**: शहरी श्रमिकों की आय बढ़ाने और उन्हें सतत आजीविका प्रदान करने के लिए एक नई योजना की घोषणा।
- **पीएम स्वनिधि योजना**: इस योजना का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें बैंकों से उन्नत ऋण, ₹30,000 की सीमा वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और क्षमता निर्माण सहायता शामिल होगी।
- **ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना**: गिग वर्कर्स को पहचान पत्र, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अर्थव्यवस्था में निवेश

- **बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)**: बुनियादी ढांचे से जुड़े मंत्रालय अगले 3 वर्षों के लिए पीपीपी मॉडल में परियोजनाओं की योजना तैयार करेंगे, राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **राज्यों के लिए बुनियादी ढांचा सहायता**: पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ की 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।
- **परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना 2025-30**: नई परियोजनाओं में ₹10 लाख करोड़ के पूंजी निवेश के लिए दूसरी परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना घोषित।
- **जल जीवन मिशन**: इस मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा और इसमें कुल निवेश बढ़ाया जाएगा।
- **शहरी चुनौती कोष**: 'विकास केंद्र के रूप में शहर', 'शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' के लिए ₹1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष स्थापित किया जाएगा, 2025-26 में ₹10,000 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित।
- **विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन**: परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के अनुसंधान और विकास के लिए ₹20,000 करोड़ की लागत से परमाणु ऊर्जा मिशन की स्थापना होगी, 2033 तक 5 स्वदेशी SMR क्रियाशील होंगे।
- **जहाज निर्माण**: जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति में संशोधन किया जाएगा। एक निर्दिष्ट आकार से बड़े जहाजों को बुनियादी ढांचा समन्वित मास्टर सूची (HML) में शामिल किया जाएगा।

- **समुद्री विकास कोष**: ₹25,000 करोड़ के कोष की स्थापना होगी, जिसमें सरकार की 49% हिस्सेदारी होगी और शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से आएगी।
- **उड़ान - क्षेत्रीय संपर्क योजना**: 120 नए गंतव्यों को जोड़ने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को वहन करने के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा। साथ ही, पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर जिलों में हेलिपैड और छोटे हवाई अड्डों को समर्थन दिया जाएगा।
- **बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा**: बिहार में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा घोषित, साथ ही पटना हवाई अड्डे की क्षमता वृद्धि और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा।
- **मिथिलांचल में पश्चिम कोशी नहर परियोजना**: बिहार में पश्चिम कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- **खनन क्षेत्र में सुधार**: टेलिंग्स से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक नई नीति लाई जाएगी।
- **SWAMIH फंड 2**: सरकार, बैंक और निजी निवेशकों के सहयोग से ₹15,000 करोड़ का कोष बनाया जाएगा, जिससे 1 लाख आवासीय इकाइयों का शीघ्र निर्माण पूरा होगा।
- **रोजगार आधारित पर्यटन विकास**: देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में चुनौती मोड के तहत विकसित किया जाएगा।

नवाचार में निवेश

- **अनुसंधान, विकास और नवाचार**: जुलाई बजट में घोषित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए ₹20,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा।
- **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स**: अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।
- **पीएम रिसर्च फेलोशिप**: आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी, जिसमें वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाएगा।
- **फसलों के लिए जीन बैंक**: भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन**: बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा।
- **ज्ञान भारतम मिशन**: शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्राहकों के साथ मिलकर 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा।

निर्यात - विकास का चौथा इंजन

- **निर्यात संवर्धन मिशन**: वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एक निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवार और मंत्रालय-विशिष्ट लक्ष्य होंगे।
- **भारतट्रेडनेट (BharatTradeNet)**: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार प्रलेखन और वित्तीय समाधान हेतु एकीकृत मंच 'भारतट्रेडनेट' स्थापित किया जाएगा।
- **ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) के लिए राष्ट्रीय ढांचा**: उभरते टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों (GCC) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया जाएगा।

सुधार - विकास का ईंधन: वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास

- **बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)**: उन कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी, जो अपना संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी।
- **NaBFID द्वारा क्रेडिट एन्हांसमेंट सुविधा**: बुनियादी ढांचे के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड्स हेतु 'आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट सुविधा' स्थापित करने की घोषणा।
- **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर**: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों और स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।
- **पेंशन क्षेत्र में सुधार**: नियामक समन्वय और पेंशन उत्पादों के विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा।
- **विनियामक सुधारों के लिए उच्च स्तरीय समिति**: सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमों, प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।
- **राज्यों के निवेश मित्रता सूचकांक**: प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों के लिए एक निवेश मित्रता सूचकांक लॉन्च किया जाएगा।
- **जन विश्वास विधेयक 2.0**: विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा।

भाग बी (PART B)

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

- **व्यक्तिगत आयकर**: नई कर व्यवस्था के तहत ₹12 लाख (यानी ₹1 लाख मासिक औसत आय) तक की आय पर कोई व्यक्तिगत आयकर देय नहीं होगा (पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर वाली आय को छोड़कर)।
- **वेतनभोगी करदाताओं के लिए छूट**: मानक कटौती ₹75,000 होने के कारण वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा ₹12.75 लाख होगी।
- **मध्यम वर्ग को राहत**: नई कर संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी हद तक कम करेगी, जिससे उनके हाथों में अधिक धन रहेगा और घरेलू खपत, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **सरल और स्पष्ट आयकर विधेयक**: नया आयकर विधेयक करदाताओं और कर प्रशासन के लिए सरल, स्पष्ट और प्रत्यक्ष भाषा में तैयार किया जाएगा, जिससे कर निश्चितता और मुकदमेबाजी में कमी आएगी।
- **प्रत्यक्ष करों में छूट**: सरकार द्वारा प्रत्यक्ष करों में ₹1 लाख करोड़ की छूट दी जाएगी।

संशोधित कर दर संरचना (Revised Tax Rate Structure)

नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित कर दर संरचना निम्नानुसार होगी:
(संशोधित कर स्लैब विवरण आगे दिया जाएगा)

Income Range	Tax Rate
0 – 4 lakh rupees	Nil
4 – 8 lakh rupees	5%
8 – 12 lakh rupees	10%
12 – 16 lakh rupees	15%
16 – 20 lakh rupees	20%
20 – 24 lakh rupees	25%
Above 24 lakh rupees	30%

नवाचार में निवेश

- **अनुसंधान, विकास और नवाचार:** निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए जाएंगे।
- **डीप टेक फंड ऑफ फंड्स:** अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना पर विचार किया जाएगा।
- **पीएम रिसर्च फेलोशिप:** IITs और IISc में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप, वित्तीय सहायता में वृद्धि के साथ।
- **फसलों के लिए जीन बैंक:** खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय जियोस्पेशियल मिशन:** आधारभूत जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जियोस्पेशियल मिशन की घोषणा।
- **ज्ञान भारतम मिशन:** 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा।

विकास के चौथे इंजन के रूप में निर्यात

- **निर्यात संवर्धन मिशन:** वाणिज्य, MSME और वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित निर्यात संवर्धन मिशन स्थापित किया जाएगा।
- **भारत ट्रेडनेट (BharatTradeNet):** व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तीय समाधान के लिए एकीकृत मंच।
- **वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा:** उभरते टियर-2 शहरों में GCC को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएंगे।

सुधारों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र का विकास

- **बीमा क्षेत्र में FDI:** भारत में संपूर्ण प्रीमियम निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी।
- **नाबफिड (NaBFID) द्वारा आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट सुविधा:** इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड को समर्थन देने हेतु।
- **ग्रामीण क्रेडिट स्कोर:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण जनता के लिए क्रेडिट स्कोर रूपरेखा विकसित की जाएगी।
- **पेंशन क्षेत्र सुधार:** पेंशन उत्पादों के नियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच की स्थापना।
- **उच्च स्तरीय नियामक सुधार समिति:** गैर-वित्तीय क्षेत्र के विनियमों, प्रमाणपत्रों, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा के लिए उच्च-स्तरीय समिति गठित की जाएगी।
- **निवेश मित्रता सूचकांक:** प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए 2025 में राज्यों के लिए निवेश मित्रता सूचकांक लॉन्च किया जाएगा।
- **जन विश्वास विधेयक 2.0:** 100 से अधिक प्रावधानों के अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए नया विधेयक लाया जाएगा।

प्रत्यक्ष कर सुधार

- **आयकर छूट:** नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख तक की वार्षिक आय (₹1 लाख मासिक) पर कोई व्यक्तिगत आयकर नहीं लगेगा।
- **वेतनभोगी करदाताओं के लिए छूट:** मानक कटौती ₹75,000 होने के कारण छूट सीमा ₹12.75 लाख होगी।
- **नई आयकर विधेयक:** करदाताओं और प्रशासन के लिए कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
- **प्रत्यक्ष कर में छूट:** लगभग ₹1 लाख करोड़ का राजस्व प्रत्यक्ष करों में छूट दी जाएगी।

आयकर दर संरचना

- **संशोधित कर संरचना:** (नई कर प्रणाली के तहत)
  - ₹0 - ₹12 लाख: **0%**
  - ₹12 - ₹18 लाख: **10%**
  - ₹18 - ₹24 लाख: **15%**
  - ₹24 - ₹30 लाख: **20%**
  - ₹30 लाख से अधिक: **30%**

अप्रत्यक्ष कर सुधार

- **औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क सरलीकरण:** सात टैरिफ दरों को समाप्त किया जाएगा, जिससे केवल आठ टैरिफ दरें शेष रहेंगी।
- **सीमा शुल्क राहत:** 36 जीवनरक्षक दवाओं को पूरी तरह से सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।
- **घरेलू निर्माण को समर्थन:** इलेक्ट्रॉनिक सामानों, लिथियम-आयन बैटरियों, जहाज निर्माण, और दूरसंचार उपकरणों के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट।

प्रमुख सरकारी योजनाओं के लिए बजट आवंटन

- **कृषि और ग्रामीण विकास:**
  - पीएम-किसान: ₹63,500 करोड़
  - मनरेगा: ₹86,000 करोड़
  - प्रधानमंत्री आवास योजना: ₹74,626 करोड़
- **शिक्षा और रोजगार:**
  - पीएम श्री स्कूल योजना: ₹7,500 करोड़
  - समग्र शिक्षा अभियान: ₹41,250 करोड़
  - कौशल विकास और अप्रेंटिसशिप: ₹13,560 करोड़
- **स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण:**
  - आयुष्मान भारत – पीएम जय: ₹9,406 करोड़
  - पोषण 2.0 मिशन: ₹21,960 करोड़
  - सामाजिक सहायता कार्यक्रम: ₹9,652 करोड़
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास:**
  - जल जीवन मिशन: ₹67,000 करोड़
  - पीएम ग्राम सड़क योजना: ₹19,000 करोड़
  - उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना: ₹2,445 करोड़

मंत्रालयों के लिए प्रमुख बजट आवंटन

- **वित्त मंत्रालय:** ₹19,39,001 करोड़
- **रक्षा मंत्रालय:** ₹6,81,210 करोड़
- **उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय:** ₹2,15,767 करोड़
- **रेल मंत्रालय:** ₹2,55,445 करोड़
- **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय:** ₹2,87,333 करोड़

समग्र वित्तीय स्थिति

- **कुल राजस्व प्राप्ति:** ₹34,20,409 करोड़
- **कुल व्यय:** ₹50,65,345 करोड़
- **वित्तीय घाटा:** ₹15,68,936 करोड़ (GDP का 4.4%)
- **राजस्व घाटा:** ₹5,23,846 करोड़ (GDP का 1.5%)
- **प्राथमिक घाटा:** ₹2,92,598 करोड़ (GDP का 0.8%)

यह बजट नवाचार, आर्थिक सुधारों, कराधान में पारदर्शिता, और बुनियादी ढांचे में निवेश के माध्यम से विकास को गति देने पर केंद्रित है।

आईसीसी पुरस्कार 2024

ICC अवार्ड्स **2024** क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों का सम्मान करता है, जिसमें पुरुष और महिला क्रिकेट में असाधारण उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। पांच दिनों तक चलने वाली घोषणाओं में, पुरस्कारों में प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के साथ-साथ **T20I, ODI** और टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम ऑफ द ईयर के चयन सहित व्यक्तिगत पुरस्कार शामिल हैं। विजेताओं और घोषणा कार्यक्रम पर एक विस्तृत नज़र डालें।

प्रमुख विजेता

उभरते क्रिकेटर विजेता

Category	Winners Name	Recognition
आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर	एनेरी डर्कसेन (दक्षिण अफ्रीका)	महिला क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें जाना जाता है।
आईसीसी इमर्जिंग मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर	कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका)	एक युवा ऑलराउंडर जो वैश्विक मंच पर प्रभावशाली प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है।

एसोसिएट क्रिकेटर्स विजेता

Category	Winners Name(Country)	Recognition
आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर	ईशा ओझा (यूएई)	महिला एसोसिएट क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान।
आईसीसी पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर	गेरहार्ड इरास्मस (नामीबिया)	नामीबिया के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में निरंतर शानदार प्रदर्शन।

वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अम्पायर

Category	Winners Name(Country)	Recognition
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अम्पायर	रिचर्ड इलिंगवर्थ	उन्हें अंपायरिंग में उत्कृष्टता और निरंतरता के लिए सम्मानित किया गया।

टी20ई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड

Category	Winners Name(Country)	Recognition
ICC महिला T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर	मेली केर (न्यूजीलैंड)	बल्ले और गेंद दोनों से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी।
ICC पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर	अर्शदीप सिंह (भारत)	अपनी घातक गति और सटीकता के लिए जाने जाते हैं, खासकर डेथ ओवरों में।

टी20आई टीम ऑफ द ईयर

Category	Players Featured
ICC महिला T20I टीम ऑफ द ईयर	कप्तान: लौरा वोल्वार्ड्ट अन्य खिलाड़ी: स्मृति मंधाना, चमारी अथापथु, हेले मैथ्यूज, नेट साइवर-ब्रंट, मेली केर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), मारिजैन कप्प, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, दीप्ति शर्मा, सादिया इकबाल।
ICC पुरुष T20I टीम ऑफ द ईयर	कप्तान: रोहित शर्मा ट्रैविस हेड, फिल साल्ट, बाबर आजम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), सिकंदर रजा, हार्दिक पंड्या, राशिद खान, वानिंदु हसरंगा, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह।

वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम

Category	Players Featured
आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम ऑफ द ईयर	कप्तान: पैट कमिंस यशस्वी जयसवाल, बेन डकेट, केन विलियमसन, जो रूट, हैरी ब्रुक, कामिंदु मेंडिस, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, मैट हेनरी, जसप्रीत बुमराह

वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एकदिवसीय टीम

Category	Players Featured
आईसीसी महिला वनडे टीम ऑफ द ईयर	कप्तान: लौरा वोल्वार्ड्ट स्मृति मंधाना, चामरती अथापथु, हेले मैथ्यूज, मारिज़ैन कप्प, एशले गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, एमी जोन्स (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन, केट क्रॉस।
आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर	कप्तान: चरित असलांका सईम अयूब, रहमानुल्लाह गुरबाज़, पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, अजमतुल्लाह उमरजई, वानिंदु हसरंगा, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, एएम ग़ज़नफ़र।

वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड

Category	Winners Name(Country)	Recognition
आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर	स्मृति मंधाना (भारत)	वनडे में मंधाना का योगदान विभिन्न श्रृंखलाओं में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण रहा।
आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर	अज़मतुल्लाह उमरज़ई (अफगानिस्तान)	वनडे में उनके प्रदर्शन ने अफगानिस्तान के क्रिकेट कद को बढ़ाने में मदद की।

टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड

Category	Winners Name(Country)	Recognition
आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर	जसप्रीत बुमराह (भारत)	जसप्रीत बुमराह ने 2024 में असाधारण प्रदर्शन करते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे दमदार गेंदबाज के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है।

Cricketer of the Year Award

Category	Winners Name(Country)	Recognition
आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड	मेली केर (न्यूजीलैंड)	उन्होंने न्यूजीलैंड को अपना पहला टी-20 विश्व कप जीतने में मदद की, जो उनके उल्लेखनीय वर्ष का मुख्य आकर्षण था।
आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड	जसप्रीत बुमराह (भारत)	खेल के सभी प्रारूपों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, समकालीन क्रिकेट में सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना

वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति ने मंजूरी दी

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने वक़्फ़ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो भारत में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन को पुनर्गठित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी सुधार है। यह विधेयक वक़्फ़ संपत्तियों के प्रशासन में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास करता है, जिससे वक़्फ़ बोर्डों और केंद्रीय वक़्फ़ परिषद के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और समावेशिता आएगी।

मुख्य प्रस्तावित बदलाव:

- **गवर्नेंस सुधार:** हाशिए पर मौजूद समुदायों, विशेष रूप से पस्मांदा मुसलमानों, को लाभ पहुंचाने के लिए वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को मजबूत करना।
- **गैर-मुस्लिम सदस्यों का समावेश:** राज्य वक़्फ़ बोर्डों में अब गैर-मुस्लिम सीईओ और कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे।
- **केंद्रीय वक़्फ़ परिषद में बदलाव:** इसमें अब एक केंद्रीय मंत्री, तीन सांसद, दो पूर्व न्यायाधीश, चार 'राष्ट्रीय ख्याति' प्राप्त व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें किसी का भी मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा।
- **संपत्ति विवाद निपटान:** राज्य सरकार को कलेक्टर के माध्यम से यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक़्फ़ की है या सरकारी भूमि। पहले यह अधिकार वक़्फ़ न्यायाधिकरण को था।

राजनीतिक विवाद और विपक्ष का रुख:

- समिति में 31 सदस्य थे, जिनमें 16 सत्तारूढ़ एनडीए से और 13 विपक्षी दलों से थे।
- सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को मंजूरी दी गई, जबकि विपक्षी दलों के 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया।
- विपक्ष ने आरोप लगाया कि वक़्फ़ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करने और सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

आगे की प्रक्रिया और संभावित प्रभाव:

- संशोधित विधेयक पर 29 जनवरी 2025 को अंतिम मतदान होगा।
- अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी 2025 तक प्रस्तुत की जाएगी।
- यह विधेयक पारित होने पर वक़्फ़ संपत्तियों के प्रशासन में सरकारी नियंत्रण को बढ़ाएगा और विवाद निपटान की प्रक्रिया में बड़े बदलाव लाएगा।
- सरकार का दावा है कि यह विधेयक हाशिए पर मौजूद मुस्लिम समुदायों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी प्रबंधन से लाभान्वित करेगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इससे वक़्फ़ बोर्डों की पारंपरिक भूमिका कमजोर हो सकती है।

विषयवार दुनिया के शीर्ष संस्थानों की सूची जारी

टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2025 जारी की गई हैं, जो विभिन्न विषयों में अग्रणी संस्थानों को प्रदर्शित करती हैं। विशेष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 में से 9 विषयों में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए उच्च शिक्षा में अपनी निरंतर उत्कृष्टता को रेखांकित किया है।

इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता: हार्वर्ड अव्वल

इंजीनियरिंग श्रेणी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 की अपनी शीर्ष स्थिति को बनाए रखा है। इस क्षेत्र में शीर्ष दस विश्वविद्यालय मुख्य रूप से अमेरिका से हैं, जो इंजीनियरिंग शिक्षा में देश की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाते हैं।

रैंकिंग इस प्रकार है:

1. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी
2. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी
3. मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT)
4. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले
5. कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक)
6. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी
7. जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
8. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजेलेस (UCLA)
9. येल यूनिवर्सिटी
10. कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी

ये संस्थान अपने अनुसंधान, नवाचार और व्यापक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए पहचाने जाते हैं। इस श्रेणी में अमेरिकी विश्वविद्यालयों का निरंतर प्रदर्शन वैश्विक इंजीनियरिंग शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है।

विषय-विशेष प्रदर्शन

आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज: MIT ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जो इस क्षेत्र में पारंपरिक पदानुक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

बिजनेस और इकोनॉमिक्स: यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया इस श्रेणी में अग्रणी है, जो व्यवसाय और अर्थशास्त्र में इसके मजबूत कार्यक्रमों और अनुसंधान को प्रदर्शित करता है।

कंप्यूटर साइंस: यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने इस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा में इसकी बढ़ती प्रभावशीलता को दर्शाता है।

एजुकेशन स्टडीज: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस श्रेणी में नेतृत्व किया है, जो शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

कानून (Law): स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस श्रेणी में भी शीर्ष पर है, जो इसके प्रतिष्ठित कानून कार्यक्रम और अनुसंधान योगदान को दर्शाता है।

लाइफ साइंसेज: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस श्रेणी में शीर्ष पर है, जो जीवन विज्ञान में इसके व्यापक अनुसंधान और योगदान को दर्शाता है।

मेडिकल और हेल्थ: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस श्रेणी में भी अव्वल है, जो चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा में इसकी उत्कृष्टता को दर्शाता है।

फिजिकल साइंसेज: कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) इस श्रेणी में शीर्ष पर है, जो भौतिक विज्ञान अनुसंधान में इसकी ताकत को रेखांकित करता है।

साइकोलॉजी: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस श्रेणी में नेतृत्व किया है, जो इसके प्रभावशाली मनोविज्ञान कार्यक्रमों और अनुसंधान को दर्शाता है।

सोशल साइंसेज: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इस श्रेणी में अग्रणी है, जो सामाजिक विज्ञान में इसके व्यापक कार्यक्रमों और अनुसंधान उत्पादन को रेखांकित करता है।

वैश्विक प्रतिनिधित्व

अमेरिकी विश्वविद्यालय शीर्ष स्थानों पर हावी हैं, लेकिन अन्य देशों के संस्थान भी प्रमुखता से उभर रहे हैं:

- **यूनाइटेड किंगडम**: यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने कंप्यूटर साइंस में और यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज ने विभिन्न विषयों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
- **एशिया**: चीनी विश्वविद्यालय, जैसे पेइचिंग यूनिवर्सिटी और त्सिंघुआ यूनिवर्सिटी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स रैंकिंग में क्रमशः चौथे और छठे स्थान पर हैं।

ये रैंकिंग वैश्विक उच्च शिक्षा परिदृश्य को प्रतिबिंबित करती हैं और विभिन्न संस्थानों की विविध ताकतों और उत्कृष्टताओं को प्रदर्शित करती हैं।

गणतंत्र दिवस परेड 2025: सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों के परिणाम घोषित

कर्तव्य पथ, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत का भव्य प्रदर्शन है। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में अनुशासन, परंपरा और कलात्मकता की शानदार झलक देखने को मिली, जहां मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियों ने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा की। परिणाम तीन विशेषज्ञ पैनलों द्वारा घोषित किए गए, और **MyGov पोर्टल** पर हुए ऑनलाइन जनमत संग्रह ने 'लोकप्रिय पसंद' (पॉपुलर च्वाइस) विजेताओं का निर्धारण किया।

सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियाँ: अनुशासन और उत्कृष्टता का प्रदर्शन

रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस की मार्चिंग टुकड़ियों ने अनुकरणीय समन्वय, सटीकता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया। विजेता इस प्रकार रहे:

न्यायाधीशों की पसंद:

- सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: जम्मू एवं कश्मीर रायफल्स
- CAPFs/अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: दिल्ली पुलिस मार्चिंग टुकड़ी

लोकप्रिय पसंद (MyGov जनमत संग्रह):

- सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: सिग्नल्स टुकड़ी
- CAPFs/अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी: CRPF मार्चिंग टुकड़ी

जम्मू एवं कश्मीर रायफल्स टुकड़ी ने अनुशासित और समन्वित मार्चिंग से जूरी को प्रभावित किया, जबकि **दिल्ली पुलिस टुकड़ी** ने उत्कृष्ट परेड ड्रिल का प्रदर्शन किया। जनमत संग्रह में **सिग्नल्स टुकड़ी** और **CRPF टुकड़ी** को जनता ने सर्वाधिक पसंद किया।

भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को दर्शाती शीर्ष झांकियाँ

गणतंत्र दिवस परेड का सबसे प्रतीक्षित हिस्सा झांकी प्रदर्शन होता है, जहां विभिन्न राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रीय मंत्रालय अपनी विशिष्ट विरासत, उपलब्धियों और परंपराओं को भव्य रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ (न्यायाधीशों की पसंद):

- **उत्तर प्रदेश – "महाकुंभ 2025 – स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास"**
  - यह झांकी **महाकुंभ 2025** की भव्यता को दर्शाती है, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसमें कुंभ मेले के आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व को प्रस्तुत किया गया।
- **त्रिपुरा – "शाश्वत श्रद्धा: त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा – खारची पूजा"**
  - यह झांकी **खारची पूजा** को प्रदर्शित करती है, जो त्रिपुरा का पारंपरिक त्योहार है। इसने आदिवासी और हिंदू परंपराओं के अद्वितीय संगम को उजागर किया।

- **आंध्र प्रदेश – "एतिकोप्पका बोम्मालु – पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने"**
  - यह झांकी **एतिकोप्पका लकड़ी के खिलौनों** की उत्कृष्ट कारीगरी को दर्शाती है, जो अपनी जैविक लाह तकनीक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी (न्यायाधीशों की पसंद):

- **जनजातीय कार्य मंत्रालय – "जनजातीय गौरव वर्ष"**
  - इस झांकी ने भारत की जनजातीय समुदायों की विरासत को प्रदर्शित किया और उनके कल्याण के लिए सरकार की पहल को उजागर किया।

विशेष पुरस्कार:

- **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) – "भारत के संविधान के 75 वर्ष"**
  - इस झांकी ने भारतीय संविधान की यात्रा को दर्शाया, जिसमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर की दृष्टि और संविधान के तहत प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।
- **'जयति जय मम भारतम' नृत्य दल**
  - इस नृत्य प्रदर्शन को भारत की सांस्कृतिक जीवंतता और देशभक्ति को दर्शाने के लिए विशेष मान्यता दी गई।

लोकप्रिय पसंद (MyGov जनमत संग्रह) में विजेता झांकियाँ

सरकार ने **MyGov पोर्टल** पर 26 से 28 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मतदान आयोजित किया, जिसमें जनता ने अपनी पसंदीदा झांकियों को चुना। परिणाम इस प्रकार रहे:

- **गुजरात – "स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास"**
  - इस झांकी ने भारत की समृद्ध विरासत और तीव्र विकास को प्रदर्शित किया, जिससे भारत की वैश्विक शक्ति बनने की यात्रा उजागर हुई।
- **उत्तर प्रदेश – "महाकुंभ 2025 – स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास"**
  - यह झांकी जनता के बीच भी अत्यधिक लोकप्रिय रही और जनमत संग्रह में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
- **उत्तराखंड – "उत्तराखंड: सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल"**
  - इस झांकी ने उत्तराखंड की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और साहसिक पर्यटन क्षमता को प्रस्तुत किया, जो इसे धार्मिक और एडवेंचर टूरिज्म के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।

केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी (लोकप्रिय पसंद):

- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय – "महिला और बच्चों की बहुआयामी यात्रा"**
  - इस झांकी ने **महिला और बच्चों की प्रगति** को दर्शाया, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।

निष्कर्ष

गणतंत्र दिवस परेड 2025 ने **भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक धरोहर** को भव्यता से प्रदर्शित किया। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की अनुशासित मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की **आकर्षक झांकियों** तक, यह आयोजन **भारत की एकता और गौरवशाली परंपराओं** का प्रतीक बना। **जनता और न्यायाधीशों दोनों की पसंद को मान्यता देने से यह परेड और भी खास बन गई।**

बीसीसीआई पुरस्कार 2024: क्रिकेट के दिग्गजों और उभरते सितारों का सम्मान

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 2025 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, जिसमें क्रिकेट के विभिन्न प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इन पुरस्कारों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पुरुष और महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।

मुख्य पुरस्कार और विजेता:

- **कर्नल सी. के. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड (पुरुष)** – सचिन तेंदुलकर
- **पोली उमरीगर अवॉर्ड - सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (पुरुष)** – जसप्रीत बुमराह
- **सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर (महिला)** – स्मृति मंधाना
- **सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू (पुरुष)** – सरफराज खान
- **सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय डेब्यू (महिला)** – आशा सोभाना
- **BCCI विशेष पुरस्कार** – रविचंद्रन अश्विन
- **ODI में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी** – स्मृति मंधाना
- **ODI में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी** – दीप्ति शर्मा
- **घरेलू क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंपायर** – अक्षय तोत्रे

उभरते हुए युवा खिलाड़ी:

- **M.A. चिदंबरम ट्रॉफी (अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक रन)** – काव्या टेओटिया
- **M.A. चिदंबरम ट्रॉफी (अंडर-19 कूच बिहार ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट)** – विष्णु भारद्वाज
- **जगमोहन डालमिया ट्रॉफी (सीनियर महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी)** – प्रिया मिश्रा
- **जगमोहन डालमिया ट्रॉफी (जूनियर महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी)** – ईश्वरी अवसारे
- **जगमोहन डालमिया ट्रॉफी (अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट)** – हेमचुदेशन जनेगनाथन
- **जगमोहन डालमिया ट्रॉफी (अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में सर्वाधिक रन)** – लक्ष्य रायचंदानी

अंडर-23 CK नायडू ट्रॉफी विजेता:

- **प्लेट ग्रुप में सर्वाधिक विकेट** – नेइज़ेखो रूपरेओ
- **प्लेट ग्रुप में सर्वाधिक रन** – हेम छेत्री
- **एलीट ग्रुप में सर्वाधिक विकेट** – पी. विद्युत
- **एलीट ग्रुप में सर्वाधिक रन** – अनीश के.वी.

रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट पुरस्कार:

- **माधवराव सिंधिया अवॉर्ड (रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में सर्वाधिक विकेट)** – मोहित जांगड़ा
- **माधवराव सिंधिया अवॉर्ड (रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में सर्वाधिक विकेट)** – तनय त्यागराजन
- **माधवराव सिंधिया अवॉर्ड (रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप में सर्वाधिक रन)** – अग्नि चोपड़ा
- **माधवराव सिंधिया अवॉर्ड (रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में सर्वाधिक रन)** – रिक्की भुई (आंध्र प्रदेश)
- **लाला अमरनाथ अवॉर्ड (घरेलू सीमित ओवर क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर)** – शशांक सिंह (छत्तीसगढ़)
- **लाला अमरनाथ अवॉर्ड (रणजी ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर)** – तनुष कोटियन

- **BCCI घरेलू टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम** – मुंबई

इस पुरस्कार समारोह में भारतीय क्रिकेट के प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया, जिससे युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

National Affairs

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित जीआई समागम के दौरान यह घोषणा की। इस आयोजन का आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने इंडिया टुडे ग्रुप के सहयोग से किया। मंत्री ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण" अपनाने की बात कही और इसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक समर्पित समिति के गठन की घोषणा की। वर्तमान में, भारत में 605 जीआई टैग जारी किए गए हैं। (Click here to read article)
- इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले दो शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह मान्यता भारत की सतत शहरी विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों शहरों को बधाई दी और शहरी विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ संतुलित करने के महत्व को रेखांकित किया। यह मान्यता वेटलैंड्स के पारिस्थितिक, सामाजिक, और आर्थिक लाभों को दर्शाती है, जो शहरों के सतत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। (Click here to read article)
- बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत 1950 के दशक में भारतीय सेना के मेजर रॉबर्ट्स द्वारा की गई थी। इसकी जड़ें यूरोपीय सैन्य परंपराओं में देखी जा सकती हैं, जहाँ सूर्यास्त के समय युद्धविराम की घोषणा की जाती थी, सैनिक अपने हथियार रख देते थे और शिविरों में लौट जाते थे। (Click here to read article)
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (CMM) को मंजूरी दे दी है, जिसमें 16,300 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह पहल उन खनिजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू की गई है जो प्रमुख तकनीकों और रक्षा उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। इस मिशन का उद्देश्य आवश्यक खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना, और भारत की संसाधन सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें स्थलीय और अपतटीय दोनों प्रकार की खनन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। (Click here to read article)

- कर्तव्य पथ, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक विरासत का भव्य प्रदर्शन है। 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में अनुशासन, परंपरा और कलात्मकता की शानदार झलक देखने को मिली, जहां मार्चिंग टुकड़ियों और झांकियों ने सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रतिस्पर्धा की। परिणाम तीन विशेषज्ञ पैनलों द्वारा घोषित किए गए, और MyGov पोर्टल पर हुए ऑनलाइन जनमत संग्रह ने 'लोकप्रिय पसंद' (पॉपुलर च्वाइस) विजेताओं का निर्धारण किया। (Click here to read article)
- भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में तेज़ वृद्धि से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई अधिसूचना के तहत, बीमाकर्ताओं को 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक प्रीमियम में 10% से अधिक वृद्धि करने से पहले IRDAI से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह कदम तुरंत प्रभाव से लागू हुआ है और इसका उद्देश्य वृद्ध लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा को किफायती और सुलभ बनाना है, जो अक्सर सीमित आय पर निर्भर रहते हैं। (Click here to read article)
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालयों में अस्थायी (ऐड-हॉक) न्यायाधीशों के रूप में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह प्रावधान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ऐसे ऐड-हॉक न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त होते हैं और उनके पास कार्यकाल के दौरान उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के समान अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी न्यायाधीश नहीं माना जाता। (Click here to read article)
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति (HLC) ने भारत के विभिन्न राज्यों में आपदा न्यूनीकरण परियोजनाओं के लिए ₹3,027.86 करोड़ की बड़ी राशि को मंजूरी दी है। इस समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। समिति ने बिजली सुरक्षा, सूखा प्रभावित क्षेत्रों और वन अग्नि प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा कर उन्हें स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य भारत की आपदा तैयारी को मजबूत करना और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करना है। (Click here to read article)
- पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन, 28 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। डॉ. एस जयशंकर 27 और 29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। जून 2024 में विदेश मंत्री के रूप में पुनः नियुक्त होने के बाद डॉ. जयशंकर की यह संयुक्त अरब अमीरात की तीसरी यात्रा थी। रायसीना डायलॉग भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो विश्व समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। (Click here to read article)

States in the News

- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के तहत लाइसेंस प्रदान किया है, जिससे इसे विदेशी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति मिल गई है। यह स्वीकृति एक अदालती हस्तक्षेप के बाद आई, जिसके तहत मंदिर के संचालन की निगरानी के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन किया गया। इस समिति ने मंदिर की विदेशी मुद्रा प्राप्तियों और अंतर्राष्ट्रीय दान स्वीकार करने की मंशा का हवाला देते हुए FCRA लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। (Click here to read article)
- हाल ही में, पुणे, महाराष्ट्र में गिलैन-बैरे सिंड्रोम (GBS) के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर तंत्रिका विकार है। इस चिंताजनक वृद्धि ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके संभावित कारणों की जांच करने और स्थिति को नियंत्रित करने के उपाय लागू करने के लिए प्रेरित किया है। यह लेख गिलैन-बैरे सिंड्रोम के बारे में, इसके लक्षणों, निदान, उपचार विकल्पों और पुणे में मौजूदा स्थिति पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। (Click here to read article)
- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू के नेतृत्व में, प्रयागराज हवाई अड्डे ने महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरते हुए, महाकुंभ महोत्सव 2025 के लिए एक आधुनिक कनेक्टिविटी हब के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रमुख विस्तारों, प्रभावी योजना और बेहतर यात्री सुविधाओं के साथ, हवाई अड्डा श्रद्धा और संस्कृति के शहर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन गया है, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लाखों श्रद्धालुओं की मेज़बानी करेगा। (Click here to read article)
- सांभर महोत्सव, जो संस्कृति, रोमांच और विरासत का एक जीवंत उत्सव है, 24 जनवरी 2025 को राजस्थान के प्रसिद्ध सांभर झील में उद्घाटित हुआ। यह 5 दिवसीय महोत्सव राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना और क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करना है। महोत्सव का उद्देश्य राजस्थानी सभ्यता की झलक प्रदान करना है, जिसमें यहां के व्यंजन, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत शामिल हैं, साथ ही झील और इसके आसपास के आकर्षणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। (Click here to read article)
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर के जनतामैदान में 'उत्कर्ष ओडिशा – मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025' का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण महजी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव, तथा भारत के विभिन्न हिस्सों से आए व्यवसायिक नेताओं ने भाग लिया। यह ओडिशा का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक कार्यक्रम है। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और ओडिशा को पूर्वी भारत का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। (Click here to read article)
- सिक्किम, भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य राज्य, अपनी खूबसूरत वादियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विशिष्ट कर-नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में सिक्किम को विशेष कर-मुक्त स्थिति प्राप्त है, जो इसे अद्वितीय बनाती है। इस लेख में सिक्किम की कर-मुक्त स्थिति के ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। (Click here to read article)
- गीता जयंती समारोह की सफलता के बाद, अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 को हरियाणा में भव्य स्तर पर मनाने की तैयारी है। हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच ने प्रेस वार्ता में घोषणा की कि यह महोत्सव 29 जनवरी से 4 फरवरी 2025 तक पिहोवा सरस्वती तीर्थ स्थल में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस महोत्सव का उद्घाटन आदिबद्री से करेंगे। (Click here to read article)
- ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना राज्यभर की महिलाओं के जीवन को बदल रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। 2024 के चुनावों से पहले भाजपा द्वारा किए गए वादों में शामिल यह योजना पहले ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालने लगी है। (Click here to read article)
- गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 30 जनवरी 2025 को पणजी में साइ-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। यह उत्सव विद्ज्ञान परिषद गोवा द्वारा आयोजित किया गया है, जो विज्ञान, नवाचार और जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। इस वर्ष का महोत्सव प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एम. स्वामीनाथन को समर्पित है। फेस्टिवल की थीम "हरित क्रांति" (Green Revolution) रखी गई है, जिसका उद्देश्य युवाओं को सतत विकास (सस्टेनेबिलिटी) की ओर प्रेरित करना है। (Click here to read article)

International Affairs

- बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपना सातवां कार्यकाल हासिल कर लिया है, जिससे उनका 30 साल का अधिनायकवादी शासन और बढ़ गया। 26 जनवरी 2025 को हुए चुनाव में लुकाशेंको ने लगभग 87% वोट हासिल किए, जिसे घरेलू विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करार दिया है। (Click here to read article)
- चाइनीज एआई स्टार्टअप डीपसीक (DeepSeek) ने सुर्खियां बटोरी हैं, क्योंकि उसने अमेरिका के एप्पल ऐप स्टोर पर ओपनएआई के चैटजीपीटी को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मुफ्त ऐप बनकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। 2023 में स्थापित, डीपसीक ने अपने उन्नत एआई मॉडलों, विशेष रूप से R1 नामक तर्कशीलता (reasoning) मॉडल के साथ तेजी से प्रसिद्धि प्राप्त की है, जो ओपनएआई की तकनीक को टक्कर दे रहा है। यह विकास यह दर्शाता है कि जेनरेटिव एआई बाजार कितना प्रतिस्पर्धात्मक बन चुका है, जिसकी अगले दशक में $1 ट्रिलियन के राजस्व तक पहुंचने की संभावना है। (Click here to read article)
- भारत और ओमान ने अपने आर्थिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर चर्चा तेज करने पर सहमति जताई है और अपने मौजूदा दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। (Click here to read article)

Books and Authors

- प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता, कवि, कलाकार, और रंगमंच व्यक्तित्व सौमित्र चट्टोपाध्याय ने भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से सत्यजीत राय के साथ अपनी फिल्मों अपुर संसार और सोनार केला के माध्यम से, अमिट छाप छोड़ी। हालांकि वे अपने प्रतिष्ठित किरदारों के लिए बंगाल और फिल्म प्रेमियों के बीच पूजनीय हैं, उनकी बहुमुखी कला के अन्य पहलुओं को व्यापक पहचान मिलनी चाहिए। उनकी बहुआयामी जीवन यात्रा को "सौमित्र चट्टोपाध्याय एंड हिज वर्ल्ड," नामक संगमित्रा चक्रवर्ती की नई जीवनी में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक अभिनेता के जर्नल, पत्र, और उनके करीबी लोगों से हुई बातचीत पर आधारित है, जो बंगाली सांस्कृतिक परिदृश्य में उनके योगदान को एक समृद्ध चित्र के रूप में सामने लाती है। (Click here to read article)

Banking/Economy/Business News

- Jio ने भारत में छोटे व्यवसायों के लिए UPI भुगतान प्रणाली में क्रांति लाने के उद्देश्य से JioSoundPay लॉन्च किया है, जो एक मुफ़्त फीचर है जिसे डिजिटल लेन-देन को और अधिक सरल और कुशल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह नई सुविधा JioBharat फोन में उपलब्ध है और हर UPI भुगतान के लिए तात्कालिक, बहुभाषी ऑडियो पुष्टिकरण प्रदान करती है, जिससे किराना स्टोर, सब्जी विक्रेता और सड़क किनारे की खानपान सेवाएं जैसे छोटे व्यापारियों के लिए लेन-देन संभालना आसान हो जाता है। यह सुविधा Jio की डिजिटल उपकरणों को आम उपयोगकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए सरल बनाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। (Click here to read article)
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन के लिए नए अनुपालन उपायों की घोषणा की है, जो 1 फरवरी 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों के तहत, यूपीआई लेनदेन आईडी अब केवल अल्फ़ान्यूमेरिक (अक्षरों और संख्याओं) होनी चाहिए, और किसी भी विशेष पात्र (@, #, $, %, आदि) का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह बदलाव सुरक्षा बढ़ाने, एकरूपता सुनिश्चित करने और भारत के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल भुगतान तंत्र की दक्षता में सुधार करने के लिए किया गया है। (Click here to read article)
- टाटा स्टील, जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माण कंपनियों में से एक है, ने देश के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। कंपनी का दावा है कि वह भारत की पहली कंपनी है जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हाइड्रोजन-कंप्लायंट पाइप्स विकसित की हैं, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। यह नवाचार वैश्विक स्तर पर स्थिर ऊर्जा समाधानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और भारत के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के साथ मेल खाता है। (Click here to read article)
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को अपना आठवां लगातार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करके इतिहास रचेंगी। वह ऐसा करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री बनेंगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 का यह बजट देश के आर्थिक ढांचे में एक और महत्वपूर्ण योगदान होगा। आइए, भारत के केंद्रीय बजट के इतिहास, रिकॉर्ड और विकास पर नजर डालते हैं, सीतारमण की इस रिकॉर्ड-ब्रेकिंग उपलब्धि और भारत के वित्तीय विवरणों के अन्य महत्वपूर्ण मील के पत्थरों को समझते हैं। (Click here to read article)
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसमें केंद्र सरकार के व्यय, राजस्व, और कर प्रस्तावों को शामिल किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है। बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह भारत के उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस यात्रा में एक अहम कदम हिंदी में केंद्रीय बजट पेश करना था, जिससे इसे आम जनता के लिए सुलभ बनाया जा सके। (Click here to read article)
- भारत के आयकर विभाग ने हाल ही में कर संधि लाभों का दावा करने के लिए प्रमुख उद्देश्य परीक्षण (Principal Purpose Test – PPT) की लागू होने वाली गाइडलाइंस पर एक मार्गदर्शिका जारी की है। यह कदम भारत के दोहरा कराधान परिहार समझौतों (DTAAs) को वैश्विक मानकों, विशेष रूप से OECD के बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) एक्शन प्लान 6 के साथ संरेखित करने के प्रयासों का हिस्सा है। (Click here to read article)
- भारत के केंद्रीय बजट (Union Budget) ने देश की आर्थिक प्रगति को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक, प्रत्येक बजट ने भारत की बदलती प्राथमिकताओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं को दर्शाया है। यह बजट न केवल विकास और सुधारों का खाका प्रस्तुत करता है, बल्कि राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में भी अहम योगदान देता है। (Click here to read article)
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो देश की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है। 10 जनवरी 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 625.87 अरब डॉलर रह गया, जो पिछले सप्ताह के 634.59 अरब डॉलर से घटा है। (Click here to read article)
- केंद्रीय बजट भारत के वित्तीय कैलेंडर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व और व्यय योजनाओं को निर्धारित करता है। हालांकि, बजट पेश किए जाने से पहले एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया जाता है: आर्थिक सर्वेक्षण। यह व्यापक रिपोर्ट पिछले वर्ष की भारत की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है और केंद्रीय बजट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नीति निर्धारकों, व्यवसायों, निवेशकों और आम नागरिकों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह सरकार की वित्तीय रणनीति की रूपरेखा तैयार करता है। (Click here to read article)
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 01 फ़रवरी 2025 को केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी, जिसमें भारत की वित्तीय रणनीति और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया जाएगा। वर्तमान में, केंद्रीय बजट एक व्यापक दस्तावेज़ है जो देश के व्यय और राजस्व संग्रह का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है। हालांकि, यह हमेशा ऐसा नहीं था। 2017 से पहले, रेलवे बजट केंद्रीय बजट से अलग प्रस्तुत किया जाता था, जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही एक परंपरा थी। (Click here to read article)
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इन परिवर्तनों से आय में वृद्धि, उपभोक्ता खर्च में वृद्धि और भारत के आर्थिक विकास में योगदान की उम्मीद है, साथ ही टैक्स संरचना को सरल बनाने और एक अधिक प्रगतिशील टैक्स वातावरण सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ पर मुख्य बदलावों का विवरण दिया गया है। (Click here to read article)

- केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कुल ₹50.65 लाख करोड़ के व्यय के साथ, यह बजट पूंजी निवेश, सामाजिक क्षेत्र में खर्च और कर सुधारों को प्राथमिकता देता है, जबकि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4% तक कम करने का लक्ष्य रखता है। बजट में रेलवे, राजमार्ग, रक्षा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। (Click here to read article)
- केंद्रीय बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को राहत देने के लिए कई आयकर छूट उपायों की घोषणा की। इन बदलावों का उद्देश्य कर भार को कम करना, फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और बचत को बढ़ावा देना है। सरकार ने कर स्लैब बढ़ाए हैं, कर-मुक्त सीमा में वृद्धि की है और छोटे व्यवसायों के लिए लाभ प्रदान किए हैं। इन उपायों से विभिन्न आय समूहों में न केवल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी बल्कि आर्थिक वृद्धि को भी बढ़ावा मिलेगा। (Click here to read article)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और जम्मू & कश्मीर बैंक पर विभिन्न नियामक अनुपालन में खामियों के कारण मौद्रिक दंड लगाए हैं। (Click here to read article)
- 2024 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की समेकित लोकपाल योजना के तहत बैंक ग्राहकों की शिकायतों में 32.81% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कुल शिकायतों की संख्या 9.34 लाख हो गई। यह वृद्धि बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक शिकायतों को लेकर बढ़ती चिंता को उजागर करती है। इन शिकायतों का मुख्य कारण सेवा में देरी, लेनदेन में त्रुटियाँ, और बैंकों द्वारा शिकायतों के समाधान में असंतोषजनक प्रदर्शन था, जो ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।(Click here to read article)
- 2024 में, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के कोने के पत्थर के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की, जो सभी डिजिटल लेन-देन का 83% हिस्सा बनाता है, जो 2019 में 34% था। यह वृद्धि UPI के तेजी से अपनाने और पारंपरिक डिजिटल भुगतान तरीकों पर निर्भरता में गिरावट को दर्शाती है। (Click here to read article)
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (National Urban Cooperative Finance and Development Corporation – NUCFDC) के गठन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में शहरी सहकारी बैंकों (Urban Cooperative Banks – UCBs) की परिचालन क्षमता को बढ़ाना है। यह पहल नियामक अनुपालन, वित्तीय स्थिरता और प्रौद्योगिकी उन्नति जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू की गई है। (Click here to read article)
- आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल ने राकेश शर्मा को तीन साल के कार्यकाल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है। यह नियुक्ति 19 मार्च 2025 से प्रभावी होगी और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की आवश्यक मंजूरी के बाद की गई है। (Click here to read article)
- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) पेमेंट्स और पाइन लैब्स ने अपनी 12 साल पुरानी साझेदारी को और मजबूत करने की घोषणा की है, जिससे डिजिटल कॉमर्स के विस्तार में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इस नई सहयोग पहल की शुरुआत 25 जनवरी 2025 को हुई, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। व्यापारियों के लिए उन्नत समाधान प्रदान करके और भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाकर, यह साझेदारी देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को बदलने का प्रयास कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों को लाभ मिलेगा। (Click here to read article)
- कर्नाटक बैंक ने 20वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन, एक्सपो और सम्मान समारोह 2024 में छह श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसे भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा आयोजित किया गया था। यह उपलब्धि बैंक की तकनीकी नवाचार और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। (Click here to read article)

Appointments/Resignations

- 24 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने जितेंद्र पाल सिंह को इज़राइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की। 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी सिंह वर्तमान में विदेश मंत्री के कार्यालय में सेवा दे रहे हैं और 2020 से विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-ईरान प्रभाग का नेतृत्व कर चुके हैं। (Click here to read article)
- मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है, ने हिसाशी ताकेउची को अपने प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। ताकेउची की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह निर्णय कंपनी के ताकेउची की नेतृत्व क्षमता में विश्वास को दर्शाता है और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में बदलाव के बीच मारुति सुजुकी को सटीक दिशा में आगे बढ़ाने की उनकी क्षमता को रेखांकित करता है। (Click here to read article)
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक (DG) के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक जारी रहेगी। (Click here to read article)

Defence News

- 21 जनवरी, 2025 को, भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में एक पर्यवेक्षक राज्य बन गया, जिसका नेतृत्व संयुक्त आयुध सहयोग संगठन (OCCAR) के तहत एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा किया गया। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन को शामिल करने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य ISTAR, समुद्री निगरानी और अन्य के लिए एक मध्यम ऊंचाई लंबी धीरज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (MALE RPAS) विकसित करना है। यूरोड्रोन के 2030 तक सेवा में आने की उम्मीद है, जिससे यूरोपीय देशों के साथ भारत का रक्षा सहयोग बढ़ेगा। (Click here to read article)

Awards and Recognitions

- श्री हरिमन शर्मा, हिमाचल प्रदेश के एक दूरदर्शी किसान, को भारतीय कृषि में क्रांति लाने के लिए प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एचआरएमएन-99 सेब की किस्म विकसित की, जिसने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सेब की खेती को सफल बनाया। यह नवाचारी, स्व-परागण और कम ठंडक वाली सेब की किस्म सेब की खेती को पारंपरिक समशीतोष्ण क्षेत्रों से परे ले गई है, जिससे किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। श्री शर्मा की यात्रा, साधारण पृष्ठभूमि से एक राष्ट्रीय प्रतीक बनने तक, जमीनी स्तर के नवाचारों की परिवर्तनकारी क्षमता को दर्शाती है। (Click here to read article)
- दूरदर्शन, भारत का राष्ट्रीय प्रसारक, को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता और शिक्षा पर अपने उत्कृष्ट अभियान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान "चुनाव का पर्व, देश का गर्व" नामक प्रभावशाली श्रृंखला और अन्य पहलों को मान्यता देता है, जो जागरूक और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई थीं। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस 2025 (25 जनवरी) को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूरदर्शन की महानिदेशक कंचन प्रसाद को प्रदान किया गया। (Click here to read article)
- जम्मू के सत्यं रिज़ॉर्ट में आयोजित एक भव्य समारोह में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के तहत "महाराजा हरि सिंह पीस एंड हार्मोनी अवॉर्ड 2024-25" का आयोजन किया गया था। यह सम्मान जम्मू-कश्मीर में सुधारों और योजनाओं के प्रति एलजी सिन्हा के योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया। (Click here to read article)

Summits and Conferences News

- पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28-29 जनवरी, 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मुख्य अतिथि थे। यूएई के विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में क्षेत्रीय भू-राजनीति, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। (Click here to read article)
- भारत 3-7 मार्च, 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की मेज़बानी करेगा। "सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता" थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में उद्यमिता और नवाचार सहयोग को मज़बूत करने के लिए ब्रिक्स देशों के लगभग 45 युवा प्रतिनिधि एक साथ आएंगे। मुख्य चर्चाएँ युवा उद्यमियों के लिए एक ढाँचा बनाने और वैश्विक बाज़ारों में उनकी भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित होंगी। (Click here to read article)

Sports News

- भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियन पनीरसेल्वम ने मलेशिया में आयोजित 9वें जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में असाधारण प्रदर्शन करते हुए खिताब जीत लिया। 22 वर्षीय इनियन, जो तमिलनाडु के एरोड से हैं, ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1.5 अंकों की बढ़त से विजयी रहे। यह जीत जनवरी में चेन्नई ओपन में उनकी पहले की जीत के बाद आई है, जिससे उनके शतरंज में उभरते सितारे के रूप में प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। (Click here to read article)
- जैनिक सिनर ने अपनी ऑस्ट्रेलियन ओपन की ताजपोशी का शानदार बचाव किया, एलेक्जेंडर ज़्वेरेव को एकतरफा फाइनल में हराकर अपने आप को टेनिस के सबसे उज्जवल सितारों में से एक साबित किया। 23 वर्षीय इटालियन खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने जर्मन प्रतिद्वंद्वी को 6-3, 7-6(4), 6-3 से हराया। अब सिनर ने इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, क्योंकि वह जिम कौरियर (1992-1993) के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन में लगातार दो बार टाईटल जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। (Click here to read article)
- स्मृति मंधाना ने 2024 में वनडे अंतरराष्ट्रीय (ODI) क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला क्रिकेट में खुद को एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। अपनी शानदार बाएं हाथ की बल्लेबाजी और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता के लिए जानी जाने वाली मंधाना ने ODIs में भारत की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह न केवल वर्ष की प्रमुख रन-स्कोरर बनीं, बल्कि कई व्यक्तिगत और टीम रिकॉर्ड भी बनाए। नीचे मंधाना के शानदार 2024 के मुख्य आकर्षण दिए गए हैं। (Click here to read article)
- भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड से नवाजा गया, जो उन्हें आईसीसी मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के रूप में मान्यता देता है। यह पुरस्कार उनके तीनों प्रारूपों में असाधारण प्रदर्शन को सम्मानित करता है, जिससे उन्होंने आधुनिक युग के महानतम तेज गेंदबाजों में अपनी जगह पक्की कर ली है। 2024 में बुमराह ने रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धियाँ हासिल कीं और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और निरंतरता से क्रिकेट जगत को प्रभावित किया। (Click here to read article)
- ऑस्ट्रेलिया ने फिर से महिला क्रिकेट में अपनी प्रभुता का परिचय देते हुए तीसरी बार लगातार ICC महिला चैंपियनशिप जीत ली। मेलबर्न में आयोजित एक भव्य समारोह में टीम को ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। यह ट्रॉफी 10 टीमों के बीच खेले गए प्रतियोगिता के विजेता को दी गई, जो ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए एक मार्गदर्शक प्रतियोगिता के रूप में कार्य करती है। कप्तान एलिसा हीली ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष और ICC निदेशक माइक बर्ड से ट्रॉफी प्राप्त की। (Click here to read article)

- खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) 2025 के पहले चरण का समापन लेह, लद्दाख में हुआ, जहां लद्दाख ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में आइस हॉकी और स्केटिंग जैसे रोमांचक खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें लद्दाख, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। (Click here to read article)
- भारत में पैरा खेलों और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आधिकारिक लोगो और शुभंकर का अनावरण किया गया। यह प्रतिष्ठित आयोजन तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा और भारत में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएगा, जहां दिव्यांग एथलीट राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। (Click here to read article)
- भारतीय क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने दिग्गज एम.एस. धोनी को पीछे छोड़ते हुए टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। हाल ही में खेले गए एक मैच में, कार्तिक ने 21 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिससे उनका कुल टी20 रन tally 7,451 रन (361 पारियों में, 409 मैचों में) हो गया। यह उपलब्धि कार्तिक को टी20 प्रारूप में सबसे स्थिर और प्रभावशाली विकेटकीपर-बल्लेबाजों में से एक के रूप में स्थापित करती है। (Click here to read article)

Schemes and Committees News

- भारत सरकार की लेटरल एंट्री योजना (पार्श्व प्रवेश योजना) को 2018 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल करके सुशासन और दक्षता में सुधार करना था। इस योजना के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप-सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बाहरी पेशेवरों की नियुक्ति की गई। हालांकि, समय के साथ इस योजना को राजनीतिक और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे इसके मूल स्वरूप में बदलाव की जरूरत महसूस की गई। आइए इसके विकास, चुनौतियों और अनिश्चित भविष्य पर एक नज़र डालते हैं। (Click here to read article)

Science and Technology News

- 25 जनवरी 2025 को, एम. मोहन को केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC) के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने डॉ. वी. नारायणन का स्थान लिया, जो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अध्यक्ष बने। (Click here to read article)
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से अपनी 100वीं लॉन्चिंग के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। सुबह 6:23 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी-एफ15 रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ और 19 मिनट बाद एनवीएस-02 नेविगेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में स्थापित कर दिया। यह मिशन भारत के 'नाविक' (NavIC) प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे उपग्रह आधारित नेविगेशन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। (Click here to read article)
- एलन मस्क एक्स को एवरीथिंग ऐप बनाने की दिशा में इस पर आए दिन कुछ न कुछ बदलाव कर रहे हैं। मस्क अब एक्स को परफेक्ट ऐप बनाने के लिए एक बड़ा कदम बढ़ा दिया है। X प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी जल्द ही फाइनेंशियल सर्विस को लॉन्च करेगी। हाल ही में कंपनी ने इसके लिए Visa के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। (Click here to read article)
- बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (BIMTECH) ने BIMCOIN नामक ब्लॉकचेन-संचालित डिजिटल मुद्रा पेश की है, जो कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेनदेन प्रणाली स्थापित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस पहल के साथ, BIMTECH भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन गया है जिसने इस तकनीक को अपनाया है, IIT मद्रास के नक्शे कदम पर चलते हुए। यह कदम अकादमिक माहौल में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है, जिससे अन्य संस्थानों के लिए एक नई मिसाल कायम होगी। (Click here to read article)
- भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण ने एक नया मील का पत्थर छू लिया है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। उन्हें एक्सिओम मिशन 4 (Ax-4) के लिए पायलट के रूप में चुना गया है, जो 2025 के वसंत में लॉन्च होने वाला एक निजी अंतरिक्ष अभियान है। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है, जो 40 साल पहले राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की विरासत को आगे बढ़ा रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण मिशन और शुभांशु शुक्ला की भागीदारी का भारत के लिए क्या अर्थ है, इसे विस्तार से समझते हैं। (Click here to read article)
- हाल के निष्कर्षों से पता चलता है कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तेजी से साइबेरिया और रूस की ओर बढ़ रहा है, जिससे नेविगेशन, पशु प्रवास और संचार प्रणाली प्रभावित हो रही है। पृथ्वी का भू-चुंबकीय क्षेत्र गतिशील है, जो बाहरी कोर में पिघली हुई धातुओं के कारण होता है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पहली बार 1831 में जेम्स क्लार्क रॉस द्वारा स्थित किया गया था और तब से यह घूम रहा है। (Click here to read article)

- भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने महिलाओं में सबसे अधिक स्पेसवॉक समय का नया रिकॉर्ड बनाया है, जिससे उन्होंने पूर्व अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विलियम्स ने अब नौ स्पेसवॉक में कुल 62 घंटे और 6 मिनट का समय दर्ज किया है। यह उपलब्धि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर के साथ अपनी हालिया एक्सट्रावेहिकुलर एक्टिविटी (EVA) के दौरान हासिल की। (Click here to read article)

Important Days News

- संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 60/7, जिसने "द होलोकॉस्ट एंड द यूनाइटेड नेशंस आउटरीच प्रोग्राम" की स्थापना की, ने 27 जनवरी को "होलोकॉस्ट पीड़ितों की स्मृति में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस" के रूप में भी मान्यता दी। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, न्यूयॉर्क, और दुनिया भर के संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में विभिन्न समारोहों और गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। (Click here to read article)
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 26 जनवरी को स्वच्छ ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों और पर्यावरण के लाभ के लिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर न्यायपूर्ण और समावेशी परिवर्तन के लिए जागरूकता बढ़ाना और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। ऊर्जा मानवता के सामने मौजूद दोहरी चुनौती का केंद्र है: (Click here to read article)
- नेशनल जियोग्राफिक डे हर साल 27 जनवरी को मनाया जाता है, जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की याद में है, जो विज्ञान, अन्वेषण और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्रों में सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक मानी जाती है। यह दिन सोसाइटी के पृथ्वी, प्रकृति और मानवता को समझने में किए गए अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने के साथ-साथ लोगों को हमारे ग्रह की रक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करता है। (Click here to read article)
- अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस (International Customs Day) हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है ताकि अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार सामानों के सुगम और सुरक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करने में कस्टम्स अधिकारियों और एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मानित किया जा सके। यह दिन कस्टम्स अधिकारियों के व्यापार प्रबंधन में योगदान को याद करता है और साथ ही उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है, जैसे राजस्व संग्रहण, आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा, और अवैध व्यापार को रोकना। यह वैश्विक उत्सव वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनाइजेशन (WCO) के सदस्य देशों द्वारा आयोजित किया जाता है, जो इस दिन के मौके पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करते हैं और कस्टम्स प्रबंधन के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं। (Click here to read article)
- भारत 28 जनवरी 2025 को अपने सबसे सम्मानित स्वतंत्रता सेनानियों में से एक, लाला लाजपत राय की 160वीं जयंती मनाएगा। 'पंजाब केसरी' या 'पंजाब के शेर' के नाम से प्रसिद्ध, लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रखर नेता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और पत्रकार थे। उनके योगदान ने भारत के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी है। यह लेख उनके जीवन, उपलब्धियों और स्थायी विरासत को उजागर करता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनकी भूमिका, आर्य समाज में नेतृत्व और भारत की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता शामिल है। (Click here to read article)
- भारतीय समाचार पत्र दिवस (Indian Newspaper Day) प्रतिवर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय समाचार पत्र दिवस (National Newspaper Day) के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पूर्व-स्वतंत्रता युग में पहले समाचार पत्र के प्रकाशन की स्मृति में मनाया जाता है और पत्रकारिता की लोकतांत्रिक भूमिका को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को समाचार पत्र पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक-राजनीतिक मामलों से अवगत कराना है। (Click here to read article)
- शहीद दिवस, जो हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, भारत में गहरा ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व रखता है। यह दिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने देश की अहिंसक स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। यह दिवस केवल गांधी जी के बलिदान को ही नहीं, बल्कि उन असंख्य वीर शहीदों को भी समर्पित है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वर्ष 2025 में, उनकी शहादत के 77 वर्ष पूरे होंगे, जो देश के प्रति कृतज्ञता और स्वतंत्रता व देशभक्ति के मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। (Click here to read article)

Obituaries News

- लतिका कट्ट, भारत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक, 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सार्वजनिक व्यक्तित्वों की विशाल मूर्तियों और बस्ट के लिए जानी जाने वाली कट्ट के काम ने प्रकृति के जैविक रूपों की सजीवता को दर्शाया। अपने पांच दशक लंबे करियर में, उन्होंने विभिन्न प्रकार के माध्यमों में काम किया, जिनमें टेराकोटा, पेपर-माचे, पत्थर और कांस्य शामिल थे, और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। (Click here to read article)

Miscellaneous News

- 2024 में प्रकाशित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट "ब्लू कार्बन और कार्बन पृथक्करण में इसकी भूमिका" ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में मैंग्रोव वनों की अपार क्षमता को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, मैंग्रोव अकेले प्रति हेक्टेयर 1,000 टन से अधिक कार्बन संग्रहीत कर सकते हैं, जिससे वे प्राकृतिक कार्बन भंडार के रूप में अत्यंत प्रभावी साबित होते हैं। यह खोज जलवायु परिवर्तन को कम करने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों में ब्लू कार्बन पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को दर्शाती है। (Click here to read article)
- केसलापुर गाँव, जो इंदरवेली मंडल में स्थित है, नागोबा जातारा के दौरान जीवंत ऊर्जा से भर गया, जब भारत के विभिन्न हिस्सों से हजारों आदिवासी और गैर-आदिवासी लोग इस वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए इकट्ठा हुए। यह सात दिवसीय महोत्सव, जो नागोबा मंदिर को समर्पित है, मेस्राम कबीला और अन्य आदिवासी समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक घटना है। मंगलवार रात से शुरू हुआ यह उत्सव, जिसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा से लगभग एक लाख भक्तों ने भाग लिया। (Click here to read article)

Static Takeaways

Sr. No	Name	Static Details
1	RBI (भारतीय रिजर्व बैंक)	राज्यपाल - संजय मल्होत्रा मुख्यालय - मुंबई
2	SBI (भारतीय स्टेट बैंक)	अध्यक्ष - चैल श्रीनिवासुलु शेट्टी प्रधान कार्यालय - मुंबई
3	SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)	एमडी - मुख्य कार्यालय - मुंबई
4	PNB (पंजाब नेशनल बैंक)	अध्यक्ष - के जी अनंतकृष्णन मुख्यालय - नई दिल्ली
5	कर्नाटक बैंक	अध्यक्ष - प्रदीप कुमार पांजा मुख्यालय - मंगलुरु
6	केनरा बैंक	अध्यक्ष - विजय श्रीरंगन मुख्यालय - बेंगलुरु
7	धनलक्ष्मी बैंक	अध्यक्ष - के.एन.मधुसूदनन प्रधान कार्यालय - केरल
8	बैंक ऑफ इंडिया	अध्यक्ष - एम. आर. कुमार मुख्यालय - मुंबई
9	IDBI बैंक	एमडी एवं सीईओ - राकेश शर्मा मुख्य कार्यालय - मुंबई
10	JIO	अध्यक्ष - आकाश अंबानी मुख्यालय - मुंबई
11	सुजुकी इंडिया	अध्यक्ष - रवींद्र भार्गव मुख्यालय - नई दिल्ली
12	टाटा स्टील	अध्यक्ष - नटराजन चंद्रशेखरन मुख्यालय - मुंबई
13	सोनी इंडिया	अध्यक्ष - सुनील नैयर मुख्यालय - नई दिल्ली
14	ZOHO	अध्यक्ष - श्रीधर वेम्बू मुख्यालय - चेन्नई
15	CRED	अध्यक्ष - कुणाल शाह मुख्य कार्यालय - बेंगलुरु
16	संयुक्त राज्य अमेरिका	राष्ट्रपति - डोनाल्ड ट्रम्प राजधानी - वाशिंगटन डी.सी.
17	नाइजर	राष्ट्रपति - अब्दौराहमाने त्चियानी राजधानी - नियामी
18	इंडोनेशिया	राष्ट्रपति - प्रबोवो सुबिआंतो राजधानी - जकार्ता
19	नेपाल	पीएम - के. पी. शर्मा ओली राजधानी - काठमांडू
20	बेलारूस	राष्ट्रपति - अलेक्जेंडर लुकाशेंको राजधानी - मिन्स्क
21	ओमान	राष्ट्राध्यक्ष - हैथा बिन तारिक राजधानी - मस्कट
22	UAE	राष्ट्रपति - मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राजधानी - अबू धाबी
23	ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद)	अध्यक्ष - जय शाह
24	BCCI	अध्यक्ष - रोजर बिन्नी

Sr. No	Name	Static Details
25	राजस्थान	राज्यपाल - हरिभाऊ बागड़े सीएम - भजन लाल शर्मा राजधानी - जयपुर
26	हरियाणा	राज्यपाल - बंडारू दत्तात्रेय सीएम- नायब सिंह सैनी राजधानी - चंडीगढ़
27	जम्मू और कश्मीर	उपराज्यपाल-मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री - उमर अब्दुल्ला राजधानी - श्री नगर
28	उत्तर प्रदेश	राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ राजधानी - लखनऊ
29	तेलंगाना	राज्यपाल - जुष्णु देव वर्मा सीएम - रेवंत रेड्डी राजधानी - हैदराबाद
30	उत्तराखंड	राज्यपाल-गुरमित सिंह सीएम-पुष्कर सिंह धामी
31	गोवा	राज्यपाल - पी. एस. श्रीधरन पिल्लई सीएम - प्रमोद सावंत राजधानी - पणजी
32	गृह मंत्री	श्री अमित शाह
33	वित्त मंत्री	श्रीमती निर्मला सीतारमण
34	वाणिज्य और उद्योग मंत्री	श्री पीयूष गोयल
35	नागरिक उड्डयन मंत्री	श्री किंजरापु राममोहन नायडू
36	मुख्य आर्थिक सलाहकार	वी. अनंत नागेश्वरन
37	MSME मंत्री	श्री गिरिराज सिंह (स्वतंत्र प्रभार)